



## राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन

### प्रलम्बि के लिये:

[औद्योगिक उत्पादन सूचकांक \(Index of Industrial Production - IIP\)](#), [राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन \(National Monetization Pipeline - NMP\)](#), [इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट \(Infrastructure Investment Trust - InvIT\)](#), [ग्लोबल वारमिंग, महामारी, स्थानिक गरीबी](#)।

### मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप एवं उसके निर्माण तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

[स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अवसंरचना में नए निवेश के लिये संसाधन उत्पन्न करने के उद्देश्य से [राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन \(National Monetization Pipeline - NMP\)](#) के तहत एक [परसिंपत्त पुनर्चक्रण अभियान](#) चलाने का निर्णय लिया है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र के परसिंपत्त पुनर्चक्रण अभियान से लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2021-22 में लगभग 0.97 ट्रिलियन रुपए और वर्ष 2022-23 में 1.32 ट्रिलियन रुपए के मुद्राकरण मूल्यों के साथ लेनदेन पूरा किया गया।

## राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन क्या है?

### परिचय:

- राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (NMP) चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2022-25) में सड़कों, रेलवे, बजिली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्राकरण क्षमता की परकिल्पना करता है।
- NMP के माध्यम से मुद्राकरण में गैर-प्रमुख संपत्तियों के निवेश के माध्यम से मुद्राकरण को छोड़कर केवल मुख्य संपत्तियों शामिल हैं। वर्तमान में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और CPSE की संपत्तियों को शामिल किया गया है।
- NMP की पहुँच को व्यापक बनाने और अंततः संघीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर संपत्तियों को शामिल करने के लिये सरकार वर्तमान में राज्यों से संपत्तियों पाइपलाइनों का आयोजन एवं संकलन कर रही है।
  - प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये, भूमि अचल संपत्तियों और अवसंरचना सहित गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्राकरण को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत [निवेश और सार्वजनिक संपत्तियों प्रबंधन विभाग \(Department of Investment and Public Asset Management - DIPAM\)](#) से [सार्वजनिक उद्यम विभाग \(Department of Public Enterprises - DPE\)](#) में स्थानांतरित किया जा रहा है।
- इस पाइपलाइन का उद्देश्य [राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन \(National Infrastructure Pipeline - NIP\)](#) के तहत वित्त वर्ष 2015 तक छह वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है।
  - NMP के लिये समय-सीमा को रणनीतिक रूप से [राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन](#) के तहत शेष अवधियों के साथ समाप्त करने के लिये निर्धारित किया गया है।

### NMP की आवश्यकता:

- लागत में वृद्धि: कुछ मामलों में, परियोजना का कार्य पूरा होने में अधिक समय लग जाता है, जिससे परियोजना की लागत इतनी बढ़ जाती है कि यह परियोजना शुरू होने के समय ही अव्यवहार्य हो जाती है।
- ओवरकैपिटिलाइजेशन: अधिकांश सरकारी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में इष्टतम इनपुट-आउटपुट अनुपात शायद ही कभी देखा जाता है, जिससे उनका ओवरकैपिटिलाइजेशन होता है।

- **संसाधनों का अनुकूलन:** लागत में वृद्धि और परियोजना में देरी आंशिक रूप से अकुशल संसाधन आवंटन तथा उपयोग के कारण होती है।
  - NMP का लक्ष्य नज्जी क्षेत्र की दक्षता और बाज़ार-संचालित दृष्टिकोण पेश करके संसाधनों का अनुकूलन करना है, जिससे इनपुट तथा आउटपुट का बेहतर संरेखण सुनिश्चित हो सके।
- **समन्वय चुनौतियाँ:** अंतर-मंत्रालयी तथा अंतर-विभागीय समन्वय की कमी से परियोजना नष्पादन में अक्षमताएँ एवं देरी का सामना करना पड़ सकता है।
  - NMP सार्वजनिक तथा नज्जी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है जिससे अवसंरचना के विकास के लिये अधिक समन्वय एवं सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
- **श्रम सुधार तथा नरिणय लेना:** श्रम सुधारों को कार्यान्वयित करने में देरी, अनुचित नरिणय लेने तथा अप्रभावी शासन से सार्वजनिक अवसंरचना की परसिंपत्तियों प्रभावित होती हैं।
- **NMP का महत्त्व:**
  - **अर्थव्यवस्था की बेहतरी:** यह एक विशेष पहल है जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, बेहतर रोज़गार के अवसर सृजित होंगे एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतसिंपर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
    - NMP **प्रधानमंत्री गतिशक्ति** से संबद्ध है जो भारत में अवसंरचना के विकास के लिये एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। गतिशक्ति एक व्यापक तथा सुदृढ़ अवसंरचना नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है जबकि NMP का लक्ष्य नई परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये मौजूदा अवसंरचना की परसिंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है।
    - एक पहल की सफलता अन्य पहल के लक्ष्यों को सुदृढ़ तथा प्राप्त करने में सहायता कर सकती है जो भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि एवं विकास में योगदान कर सकती है।
  - **कम उपयोग वाली सार्वजनिक परसिंपत्तियों का उपयोग:** NMP गैर-रगनीतिक निम्न प्रदर्शन करने वाली सरकारी स्वामित्व वाली परसिंपत्तियों से नष्क्रिय पूंजी का उपयोग करने का समर्थन करता है।
    - यह इस प्रकार प्राप्त धन को नई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पुनर्विनिवेश करने और ग्रीनफील्ड बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसी परसिंपत्तियों के संवर्द्धन की भी परकल्पना करता है।
- **उपलब्धियाँ एवं अपेक्षाएँ:**
  - **खनन क्षेत्र:** वर्ष 2023-24 में परसिंपत्तियों के मुद्रीकरण का केंद्र खनन क्षेत्र, विशेष रूप से कोयला ब्लॉक तथा अन्य खदानें रही हैं।
    - वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र में उपलब्धि लगभग 55,000-60,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो कि इसके 8,726 करोड़ रुपए के प्रारंभिक लक्ष्य से अधिक है।
    - वित्त वर्ष 2023 का लक्ष्य 6,060 करोड़ रुपए से बढ़कर 37,500 करोड़ रुपए हो गया जिसमें लगभग 68,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई।
    - खनन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022 में 3,394 करोड़ रुपए की तुलना में लक्ष्य से अधिक, 68,000 करोड़ रुपए अर्जित किये।
  - **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): ब्राउनफील्ड परसिंपत्तियाँ पुनर्चक्रण (Brownfield Asset Recycling)** में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में NHAI को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है।
    - यह उपलब्धि टोल ऑपरेट ट्रांसफर (TOT), प्रतभूतिकरण तथा **इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर (InvIT)** मॉडल के मशिरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
  - **वित्त वर्ष 2024 में अन्य क्षेत्रों हेतु अपेक्षाएँ:**
    - ऊर्जा उत्पादन तथा पारेषण क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में 15,300 करोड़ रुपए के अपने संयुक्त लक्ष्य को पूरा किया जिसके वित्त वर्ष 2024 में 26,700 करोड़ रुपए के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले लगभग 20,000 करोड़ रुपए की उपलब्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है।
    - **रेलवे**, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 के लिये 44,907 करोड़ रुपए से घटाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था, वित्त वर्ष 2023 में 8,000 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 8,000-10,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने की संभावना है।
      - हालाँकि रेलवे ने स्टेशनों जैसी प्रमुख परसिंपत्तियों के मुद्रीकरण में अत्यधिक प्रगति नहीं की है कतिु यज्ञे रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास, गतिशक्ति (Gati Shakti) माल दुलाई टर्मिनलों एवं रोलिंग स्टॉक संबंधी संव्यवहार की पूर्ति करेगा।
    - **तेल और गैस क्षेत्र** ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है तथा मार्च 2024 तक यह 8,000 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

## NMP से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **करदाताओं के धन जारी करना:** करदाताओं ने सार्वजनिक संपत्तियों पर संभावित दोहरे शुल्क के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन परसिंपत्तियों के निर्माण के लिये वित्तपोषण के बाद, अब उन्हें नज्जी संस्थाओं को उनके मुद्रीकरण के बाद भुगतान के माध्यम से उनका उपयोग करने हेतु अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता है।
  - चुनौती आरोपों के इस कथित दोहराव से निपटने और इन परसिंपत्तियों के प्रबंधन तथा उपयोग में सार्वजनिक निवेश एवं नज्जी भागीदारी के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने में नहिंति है।
- **संपत्ति और मुद्रीकरण का चक्र:** NMP द्वारा नई संपत्ति सृजित होने तथा बाद में सरकार के लिये देनदारी हेतु उसका मुद्रीकरण करने संबंधी एक दुष्चक्र निर्मित होने की काफी संभावना है।
- **संपत्ति-विशिष्ट चुनौतियाँ:** इसमें गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर, बजिली क्षेत्र की परसिंपत्तियों में वनियमिति टैरिफि, चार लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में नविशकों के बीच कम रुचि तथा इकाई हस्सिंदारी रखने वाले कई हतिधारक शामिल हैं।
- **एकाधिकार:** NMP की एक महत्त्वपूर्ण आलोचना यह है कि **हस्तांतरण से एकाधिकार उत्पन्न होगा, जिससे कीमत में वृद्धि होगी।**
  - स्वामित्व के सुदृढ़ीकरण से विशेष रूप से राजमार्गों और रेलवे लाइनों के मामले में एकाधिकार हो सकता है। यह चिंता कम प्रतसिंपर्द्धा और बाज़ार की गतिशीलता की संभावना पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से अंतमि उपयोगकर्ताओं के लिये उच्च लागत हो

सकती है।

## आगे की राह

- नविशकों, सरकारी एजेंसियों और जनता सहति हतिधारकों के बीच वशिवास बनाने के लयि परसिंपत्ता भुद्रीकरण परक्रयि में पारदर्शति बढाने की आवश्यकता है।
- आर्थकि वकिस, रोजगार सृजन और बेहतर बुनयिदी ढाँचे के संदरभ में परसिंपत्ता भुद्रीकरण के लाभों के बारे में बताइये।
- उभरती चुनौतयिों और अवसरों से नपिटने के लयि नीत ढाँचे को लगातार परषिकृत तथा अदयतन करना अनविर्य है।
- एक सहायक वनियामक वातावरण सुनशिचति करें जो नजी कषेत्र की भागीदारी और नविश को प्रोत्साहति करें।
- परसिंपत्ता भुद्रीकरण परयिोजनाओं के परदर्शन को ट्रैक करने के लयि एक मज़बूत नगिरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापति करें।

## UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न1. श्रम प्रधान नरियातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में वनिरिमाण कषेत्रक की वफिलता का कारण बताइए। पूंजी-प्रधान नरियातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान नरियातों के लयि उपायों को सुझाइए। (2017)

प्रश्न2. हाल के समय में भारत में आर्थकि संवृद्धि की प्रकृति का वरणन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर कयिा जाता है। क्या आप इस वचिर से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजयि। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/national-monetisation-pipeline-3>

